fssai **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**

विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक

प्रेस नोट

स्मार्ट शहर से खाद्य स्मार्ट शहर

भारत में ''खाद्य स्मार्ट शहर'' बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपनी एक अनोखी पहल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के मध्य एक नूतन फ्रेमवर्क पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श का संचालन किया। खाद्य स्मार्ट शहरों में शहरी विकास मंत्रालय के ''स्मार्ट सिटी'' मिशन की तर्ज पर खाद्य प्रणालियों के लिए आद्यांत समाधान होंगे।

दिनांक 2 मई, 2017 को एफ.एस.एस.एआई और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय में संयुक्त रूप से आयोजित खाद्य स्मार्ट सिटीज पर बहु-हितधारकीय विचारोत्तेजक कार्यशाला में खाद्य स्मार्ट शहर परियोजना का ढाँचा उद्घाटित करने के फ्रेमवर्क और प्रणाली पर चर्चा की गई। बैठक में लुधियाना, अजमेर, जयपुर, गुड़गाँव और भुबनेश्वर के प्रतिनिधियों सहित स्मार्ट शहरों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विश्व भर में अपनाई जा रही उत्तम रीतियों को साझा करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और विद्वानों ने भी भाग लिया। इनमें यू. के की फूड फाउंडेशन, नार्वे और स्वीडन की ई.ए.के फाउंडेशन, बरमिंघम सिटी कौसिंल का एक प्रतिनिधि और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रोपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर एलन डैंगोर शामिल थे।

श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि भोजन को वायु और पानी की भाँति प्राय: सुनिश्चित मान लिया जाता है और जीवन-चक्र इसी पर आधारित होने के बावजूद इसे नगर आयोजना में अधिकतर अनदेखा कर दिया जाता है। खाद्य प्रणाली प्रबंधन को स्मार्ट शहर के दिशा-निर्देशों में शामिल करने का अब सुनहरा अवसर है। भोजन को मद्देनजर रखने से नगर आयोजकों को सुरक्षित और पोषक आहार के माध्यम से नागरिकों का स्वास्थ्य और प्रसन्नता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक ढाँचा तैयार करने हेतु अनेक दिलचस्प अवसर मिल जाते हैं।

भारत में शहर विकास-वाहक हैं और 60 से अधिक शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। इस द्रुत शहरीकरण से खाद्य की पर्याप्तता, खाद्य की गुणता और पर्यावरण संबंधी कई अहम् मुद्दे उठ खड़े हुए हैं । इनसे निपटने का एक उपाय स्मार्ट शहर के डिजाइन में टिकाऊ खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रणालियाँ शामिल करना और खाद्य स्मार्ट शहर बनाना है। ब्रेंट लोकेन, साइंस लायॅजन ऑफिसर, ई.ए.टी फाउंडेशन ने श्रोताओं को बताया कि खाद्य स्मार्ट सिटी की अवधारणा अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास के प्रारंभिक चरण में है और भारत के पास लोगों की विचारधारा को इस अत्यावश्यक मुद्दे की ओर अभिमुख करने हेतु अग्रणी भूमिका निभाने के अवसर हैं।

कार्यशाला में एफ.एस.एस.ए.आई ने कार्रवाई योग्य मुद्दों का स्पष्ट वर्णन करते हुए चार मुद्दों वाला वह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसके आधार पर शहर देश भर में परिवर्तन लाने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं। चार मुद्दों वाले दृष्टिकोण में आपूर्ति की श्रृंखला में सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने, आहार में सुधार करने, उपभोक्ताओं में सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाने और अधिक भोजन प्रबंधन एवं खाद्य क्षति की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए अभियान छेड़ने, प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ आरंभ करने से इनके पूरे देश में अनुकरण के लिए ये सभी शहरों में परिवर्तन के माड्यूल का काम कर सकते हैं और एफ.एस.एस.ए.आई ने इनमें से कई मुद्दों पर पर्याप्त प्रारंभिक कार्य पहले ही कर लिया है, जिन्हें खाद्य स्मार्ट शहर बनने के इच्छुक किसी भी शहर में लागू किया जा सकता है।

कार्यशाला के भागीदार विचारों से भरकर और अपने शहर के लिए एक स्पष्ट कार्रवाई योजना लेकर गए। श्री अनुपम मिश्रा, शहरी विकास मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे शहरों के वास-योग्य सूचकांक में खाद्य आधारित मानदंड शामिल करने का सुझाव दिया, जबकि लुधियाना स्मार्ट सिटी की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री सुरभि मलिक ने कहा कि वे उनके यहाँ विकसित किए जा रहे नए नागरिक सहयोग और फीडबैक पोर्टल में अब भोजन को भी शामिल करने के लिए प्रेरित हुई हैं।

कार्यशाला इस निर्णय के साथ समाप्त हुई कि खाद्य स्मार्ट शहरों के ढाँचे को और आगे सटीक बनाकर उसे खाद्य स्मार्ट शहर बनने के इच्छुक देश भर के शहरों को परिचालित किया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में खाद्य प्रबंधन और नगर आयोजना के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया।